ग्रामीण किसानों के उद्योगीकरण में मदद
कृषि कुंभ (जुलाई 2023),
खण्ड 03 भाग 02, पृष्ठ संख्या 136

ग्रामीण किसानों के उद्योगीकरण में मदद

सचिन कुमार वर्मा[1], डॉ० सुप्रिया[2] एवं आदित्य भूषण श्रीवास्तव
[1,3]शोध छात्र, [2]प्राध्यापक,
[3]आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवम् प्रोधोगिकी विश्वविधालय, कुमारगंज अयोध्या ,उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: sachinssv974@gmail.com

स्वतंत्रता के बाद से अब तक, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में कृषि पर निर्भर रही है। बड़े हिस्से में देश की आबादी को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित किया जाता है और इसका सीधा असर कृषि पर पड़ता है। यहां तक कि वर्तमान में भी, करीब 70% लोग खेती करके अपना जीवनयापन करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आमतौर पर अत्यंत पिछड़ी हुई है। बड़े शहरों के उद्योगीकरण के बीच, यह मार्जिनल किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। मार्जिनल किसान वे किसान होते हैं जो अपने छोटे–मोटे जमीन के साथ काम करते हैं और अपने परिवार के जीवन को चलाने के लिए संकटमय स्थिति में होते हैं। उनके पास कम संसाधन होते हैं और यहां तक कि कई बार उनकी जमीन का भी स्वामित्व साबित करना मुश्किल होता है। ये किसान अक्सर बड़े किसानों और उद्योगों के तहत काम करते हैं और उनसे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं। उनकी आय अत्यंत अस्थायी होती है और यह किसानों को अपनी कृषि कार्यक्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि की दिशा में बाधा बनती है। इन मार्जिनल किसानों की समस्याओं को समझते हुए, सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता और उद्योगीकरण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, मार्जिनल किसानों को उद्योगीकरण के लिए आवश्यक संसाधन, विपणन में सुधार, तकनीकी सहायता और व्यापारिक मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान की जाती है।

एक महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेएसएन) योजना। इस योजना के तहत, मार्जिनल किसानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसके अलावा, सरकार ने कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगीकरण योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि विमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, तकनीकी सहायता कार्यक्रम आदि प्रदान की हैं। मार्जिनल किसानों के लिए उद्योगीकरण के लिए अधिक चर्चा की आवश्यकता है। उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों, सुरक्षित खेती विधियों, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की खेती, विपणन के नए तरीकों और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सरकार और संबंधित संगठनों को इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और व्यापारिक मार्गदर्शन का आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा, मार्जिनल किसानों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने में मदद की आवश्यकता होती है। बैंकों को सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें वित्तीय सहायता, ऋणों की सुविधा, व्यापारिक मार्गदर्शन और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मार्जिनल किसानों के उद्योगीकरण के लिए सामाजिक और राजनीतिक समर्थन भी आवश्यक है।

ग्रामीण समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय नेताओं को मिलकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों में सहायता करनी चाहिए। उन्हें उद्योगीकरण के लाभों और मार्जिनल किसानों की महत्वपूर्णता को साझा करने के लिए जागरूक करना चाहिए। मार्जिनल किसानों के उद्योगीकरण के माध्यम से, उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की संभावनाएं मिलेंगी। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विकास बढ़ेगा, बल्कि देश की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए, सरकार, सामाजिक संगठन, बैंक और उद्योग को संगठित रूप से मिलकर मार्जिनल किसानों के उद्योगीकरण की मदद करनी चाहिए।